

डीएम की अध्यक्षता में 'किसान दिवस' आयोजित

- जल्द से जल्द कराया जाये किसानों की समस्याओं का निराकरण: जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह
 - किसान दिवस पर अधिकारियों ने दी किसानों को योजनाओं की जानकारी
 - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस पर अधिकारियों ने सुनी किसानों की समस्याएं

संवाददाता



बढ़ोतरी करना इत्यादि समस्याओं से जिलाधिकारी सहित उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा किसानों को अवगत कराया गया कि पिछले किसान दिवस पर सुनी गई समस्याओं का लगभग निराकरण कराया जा चुका है। साथ ही किसानों का गन्ना भुगतान तीन भागों में तीन महीनों के अन्दर कराया जायेगा। बाढ़ के कारण किसानों के हुए नुकसान की जांच के शीघ्र की करवाई जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए जल्द ही और भी गौशालाओं का निर्माण करवाया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को आदेशित किया गया कि किसानों द्वारा प्राप्त समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण किया जाये। किसानों का बाढ़ से हुए नुकसान की जांच के लिए टीम गठित की जाये। जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा किसान दिवस में उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेशित किया गया कि कृषकों की प्राप्त शिकायतों का निराकरण करते हुए, शिकायतकर्ता को समय पर अवगत करा दें। साथ जिलाधिकारी ने आदेश दिये कि अगले माह में होने वाले किसान

दिवस में विद्युत विभाग के समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता तथा सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी अवश्य प्रतिभाग करें। मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा किसानों को अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा और भी गऊशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक गांव के न्याय पंचायतों को निर्देशित किया कि किसान दिवस के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर बनाया जाये जिससे न्याय पंचायत के

नां द्वारा किसानों की समस्या के बारे में पूछा जाये, कृषि विज्ञानिकों माध्यम से किसानों की छोटी से छोटी समस्याओं का समूचित वरण के निर्देश दिये। श्री महेश गार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अवगत कराया गया कि पशु न विभाग द्वारा ग्रामों में पशुओं टीकाकरण कराया जा रहा है। कृत्रिम गभार्थान से सम्बन्धित नकारी दी गयी। उप निदेशक कृषि किसानों को अवगत कराया कि नकी कृषि भूमि 01 जनवरी, 23 से पूर्व की है या विरासत में

यूपी में ज्यादा विदेशी निवेश लाने के लिए बनेगी नई नीति, मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा बैठक

लखनऊ। वैश्विक निवेश सम्मेलन में आए रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से उत्साहित योगी सरकार ने अब अधिक से अधिक विदेशी निवेशकों को लाने की तैयारी की है। यूपी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए अलग से नीति लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास को लेकर हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। सीएम आवास पर हुई बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के अलावा करीब एक दर्जन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेश सम्मेलन के प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यूपी को उद्योगों का गढ़ बनाने और विश्व स्तर पर धमक बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अलग से नई नीति लाने या वर्तमान औद्योगिक नीति में अलग से व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जल्द ही भूमि पूजन समारोह की तारीख भी तय होगी। खास बात ये है कि पिछले छह साल में यूपी विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। जहां 25 से ज्यादा देशों ने 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक प्रदेश में विदेशी कंपनियों की करीब 50 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बैठक में औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता में कोई कमी न आने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा लैंड बैंक के सृजन और आवंटन की रिपोर्ट रखी गई। औद्योगिक निवेश नीति के तहत फास्ट ट्रैक आवंटन, फार्मा पार्क और बुदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन पर भी चर्चा हुई।

सीएम योगी के प्रयासों का प्रतिफल, गरीबी हटाने में सबसे आगे रहा यूपी

- 36 राज्यों और कद्र शासित प्रदेशों में सवाधिक यूपी में घटी गरीबों की संख्या
 - नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2015-16 और 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोग गरीबी से उबरने में कामयाब रहे
 - रिपोर्ट में कई पैरामीटर्स पर यूपी में गरीबों की स्थिति में हुआ उल्लेखनीय सुधार

संवाददाता

लखनऊ । उत्तर प्रदेश का यागा सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों की आय बढ़ाकर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों का सुखद परिणाम सामने आया है। नीति आयोग की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच जहां भारत में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से राज्या, कद्र शासत प्रदेश और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों का नंबर यूपी के बाद आता है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में, 2015-16 और 2019-21 के बीच 3,42,72,484 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। परिणामस्वरूप, प्रदेश में गरीबी में रहने वाले लोगों का अनुपात 2015-16 में 37.68% से घटकर 2019-21 में 22.93% हो गया है। उत्तर प्रदेश के 2015-16 में 44.29% से घटकर 2019-21 में 26.35% हो गया, जबकि शहरों में यह 2015-16 के 17.72% से हटकर 2019-21 में 11.57 पर आ गया। गरीबी के साथ ही यूपी में गरीबों की हेत्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग संबंधित पैरामीटर्स में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में न्यूट्रीशन से वर्चित गरीबों की संख्या 30.40% थी जो 2019-21 में घटकर 18.45% पर आ गई। इसी तरह, बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। 2015-16 में यह 3.81% थी जो 2019-21 में घटकर 2.20% पर आ गई। हुआ और 2015-16 के 25.20% से घटकर यह 2019-21 में 15.97% पर आ गई। स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग के तहत 2015-16 में कुकिंग फ्लू से वर्चित गरीबों का प्रतिशत 34.24 था जो 2019-21 में 17.95% रह गया। 2015-16 में 2.09% पीने के पानी से वर्चित थे जो आंकड़ा 2019-21 में घटकर 0.93% रह गया। गरीबी में सर्वाधिक कमी वाले दस जिले: महाराजगंज- 29.64, गोंडा- 29.55, बलरामपुर- 27.90, कौशाल्या- 25.75, खीरी-25.33, श्रावस्ती- 24.42, जौनपुर-26.65, बस्ती- 23.36, गाजीपुर- 22.83, कुशीनगर- 22.28, चिक्रिकूट- 21.40।

ग्रामाण क्षेत्रों में गरीबों का अनुपात 2015-16 में 44.29% से घटकर 2019-21 में 26.35% हो गया, जबकि शहरों में यह 2015-16 के 17.72% से हटकर 2019-21 में 11.57 पर आ गया। गरीबों के साथ ही यूपी में गरीबों की हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग संबंधित पैरामीटर्स में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में न्यूट्रीशन से वीचत गरीबों की संख्या 30.40% थी जो 2019-21 में घटकर 18.45% पर आ गई। इसी तरह, बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। 2015-16 में यह 3.81% थी जो 2019-21 में घटकर 2.20% पर आ गई।

रनल हल्थ में भा काफी सुधार आ और 2015-16 के 20.20% से घटकर यह 2019-में 15.97% पर आ गई। इंडर्ड ऑफ लिविंग के तहत 2015-16 में कुकिंग फ्यूल सेवत गरीबों का प्रतिशत 34.24 था 2019-21 में 17.95% रह गया। 2015-16 में 2.09% पीने के पानी सेवत थे जो आंकड़ा 2019-21 में कर 0.93% रह गया। गरीबी में साधिक कमी वाले दस जिलेः राजगंज- 29.64, गोंडा- 29.55, नरामपुर- 27.90, कौशाम्बी- 27.75, खीरी- 25.33, श्रावस्ती- 24.42, जौनपुर- 26.65, बस्ती- 23.36, गाजीपुर- 22.83, कुशीनगर- 22.28, चिक्रूट- 21.40।

ਸੀਏਮ ਨੇ ਏਨਐਮ ਸ਼ਵਾਈ ਕਾਰਕਤ੍ਰਿਧਿਆਂ ਕੋ ਨਿਯੁਕਿ ਪੜ ਵਿਤਾਇਆ ਕਿਏ

- मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जी के विजयन के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग की 1,573 ए०एन०एम० स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा : मुख्यमंत्री ● अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों का चयन किया गया ● नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार विगत 06 वर्षों में ३०प्र० बीमारू राज्य की श्रेणी से उबर कर विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर ● प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप गरीबी की दर लगभग 11 से 12 फीसदी रह गई ● प्रदेश में विगत 06 वर्षों में अनेक मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की 1,573 ए०एन०एम० स्वास्थ्य कार्यक्रियां को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। विगत डेढ़ वर्षों में यह 19वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है, इस प्रक्रिया में लगभग 58 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत जनपदों के लिए चयनित 1,573 ए०एन०एम० स्वास्थ्य कार्यक्रियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 15 ए०एन०एम० स्वास्थ्य कार्यक्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। विभाग द्वारा मिशन रोजगार पर तैयार की गयी एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का कार्यक्रम मिशन रोजगार का कार्यक्रम होने के साथ-साथ मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम है। एक साथ इतनी बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मिशन शक्ति का अभियान महिला सशक्तिकरण करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त ए०एन०एम० स्वास्थ्य कार्यक्रियां पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभिवृद्धि करने, उसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देश के लिए नजीर बनाने में अपना योगदान देंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियुक्ति और नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ सम्पन्न की जा रही है। यदि कोई अधिर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है या उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहता है और योग्यता रखता है, तो उसे प्रदेश में

कार्य करने का अवसर मिलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ करना शेष है। राष्ट्रीय औसत का लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात अब हमें अन्तरराष्ट्रीय मानकों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। ह्याएक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज़ जैसे प्रयास इसी दिशा में किए जा रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नरसिंग, पैरामोडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। लगातार इस दिशा में कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में कार्य करने की बहुत सारी सम्भावनाएँ हैं। हमें अपने आपको इसके लिए तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े हुए जो भी आयोग और बोर्ड हैं, उन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तकनीकी का प्रयोग करते हुए सारी प्रक्रियाएँ पारदर्शी रूप से सम्पन्न की जा रही हैं। देश के नौजवानों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, उनमें प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। किसी भी आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया का कोई भी मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है। प्रदेश सरकार का किसी भी आयोग या

बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शन और निष्पक्ष तरीके से कराना आयोग और बोर्ड का अधिकार है। वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार विगत 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उबर कर विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या लगभग पौने छः करोड़ थी। प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप गरीबी की दर 37.68 प्रतिशत से घटकर 2019-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही 22 प्रतिशत करने में सफलता प्राप्त की है। विगत 02 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीब कल्याण आदि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप गरीबी की दर लगभग 11 से 12 फीसदी रह गई है। जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूँ, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, सम्पल, लखीमपुर खीरी, हरदोई और बांदा आदि जनपदों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि

र जल संसाधन, स्किल
ललपमेन्ट, रोजगार जैसे विभिन्न
मीटर तथ किए गए हैं। इन
पांडों में एक अभियान के तहत
विकास खण्डों में एक आधानमंत्री जी के
तात्व और नीति आयोग के
पर्दशन में प्रथम 08 आकांक्षात्मक
पांडों में परिवर्तन देखने को मिला
प्रदेश सरकार ने 100
कांक्षात्मक विकास खण्डों को भी
निहित किया। इन विकास खण्डों में
भैन्न विभागों ने शत-प्रतिशत
पावर की आपूर्ति करते हुए
कांक्षात्मक विकासखण्डों की
प्रति से उभारने के जो प्रयास हुए
उसके परिणाम सभी को देखने
मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने
इसे कि पहले गोरखपुर, बस्ती,
पोटान, आजमगढ़, मण्डल में
मात्र मेडिकल कॉलेज जनपद
खण्डों में था। नेपाल और बिहार
मरीज भी इसी मेडिकल कॉलेज
चिकित्सा के लिए आते थे।
होने इस दुर्व्यवस्था के लिए सड़क
लेकर संसद तक निरंतर आवाज
ई। अब जनपद गोरखपुर के
0304020 मेडिकल कॉलेज में
नानुकूलित सभागार, वॉर्ड आदि
इलाज के लिए आने वाले प्रत्येक

औसत के समकक्ष लाने में सफलता प्राप्त हुई है। कुछ मामलों में प्रदेश की उपलब्धियां राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हैं। नेशनल फैमिली हेल्पिंस सर्वे-4 के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 51 फीसदी टीकाकरण के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 70 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में पूरी प्रतिरक्षण का कवरेज 98 प्रतिशत है। इसमें आपकी अहम भूमिका होती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017-18 स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर कार्यक्रम चलाया, परिणामस्वरूप इंसेफेलाइटिस बीमारी प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। एक भी बच्चे की मौत इन बीमारी से नहीं होती। जनप्रीत गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस से कमज़ोर तबके के बच्चे अस्सम काल कवलित होते थे।

गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा : सोशल मीडिया पर लाइव करते समय युवक पर चढ़ी भाजपा नेता की कार

गाजियाबाद। गाजियाबाद में देर सार तीन युवक सड़क पर चढ़ियों बना रहे थे वहाँ राजनगर पुल से नीचे उतर रहे एक कार सवार ने चढ़ियों बना रहे युवक पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। कार पर भाजपा का झड़ा लगा था और उस पर विधायक लिया है। वारदात कैमरे में कैद हो गई। युवकों के मृतबिक कार चालक नशे की हालत में लग रहा था। आपको बता दें कि राजनगर पुल पर युवक चढ़ियों बना रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार युवक को रोटेट हुए और अगे चली गई। युवक कार के नीचे फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई।



युवक वहाँ चढ़ियों बना रहे थे, इसलिए ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। युवकों के मृतबिक कार चालक नशे की हालत में लग रहा था। कार की स्पीड भी बहुत अधिक थी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। कार का नंबर क्र. 14 श्लष्ट 4854 है। इस घटना पर भाजपा का बैनर लगा है। जिस पर विधायक लिया हुआ है। घटना के समय कार चालक नशे की हालत में लग रहा था। इस घटने के बाद पुलिस को 112 पर कॉल कर बुलाया गया। फिलहाल थाना कविनगर पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

गाजियाबाद में एटीएम फॉड करने वाले अंर्याजीय गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार, 10 फर्जी एटीएम कार्ड व नगदी बरामद

गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस कमिशनरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो अंर्याजीय एटीएम कार्ड बदलकर ठाकी करने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को इनके पास से 10 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई है। ये भोले-भाले लोगों से उनका एटीएम बदलकर फॉड करते थे और कई एटीएम मशीन में फेवीकिन लगा कर लोगों के कार्ड वासिल करते थे। क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए अरोपियों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर चढ़ियों देख कर एटीएम फॉड करना सीखा और अन्य साथियों को ट्रेंड किया। पकड़े गए संदिप और गैरव मिश्रा ने पूछाया में बताया कि संदिप की पहले मोबाइल की ढुकान थी और उसके ऊपर कर्जा होने की वजह से वह यूट्यूब पर चढ़ियों देखकर एटीएम फॉड को सीख गया और अन्य साथियों को ट्रेंड किया। पकड़ा गया दुसरा अरोपी गैरव मिश्रा एयरटेल कंपनी में काम कर चुका है और उस अपेक्षी की अच्छी नॉलेज है। इन लोगों ने अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और अन्य इलाकों में एटीएम फॉड किया है।



14 साल की बच्ची की हत्या, घर से 25 लाख गायब, हिरासत में परिवार का करीबी

नोएडा। नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर में अकेली 14 साल की बच्ची की किसी ने हत्या कर दी और उसके बाद 25 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और परिवार के परिवर्तत एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मृतबिक मेरठ के रसने वाले डॉक्टर सुदर्शन बैरागी फिलहाल नोएडा के सरस्वती एनक्लेव, सेक्टर-93-गेज़ा में अनुष्ठान पाली बिल्डिंग चलते हैं। सुदर्शन सबूत को 14 वर्ष की बेटी स्थानीयों को अकेले घर पर छोड़कर, पती और दो बच्चों के साथ बिल्डिंग चले गए थे। जब वह दोपहर करीब 1.30 बजे वापस लौटे तो पाया कि उनकी बेटी के गले में चुनी लगी हुई थी। बच्चे के मुह में बल्कि सा भड़ा आया था। जिसका बाद उसे तुरत पास के फेलिक्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जहाँ डॉक्टर ने उसे तुरत घोषित कर दिया। डॉक्टर सुदर्शन ने बताया कि उनके घर पर रखे लगभग 25 लाख रुपये गायब थे। अपील कुछ दिनों पूर्व एक फ्लैट की बिक्री की थी। यह उसी प्लाट के पैसे थे, घर का सारा सामान बिखरा था।

